(कितने मामले जिला-वार श्रम न्यायालयों और उच्च न्यायालय में लम्बित/विचारधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गत एक दशक के दौरान लम्बित मानलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ग) क्या राज्यों में लम्बित मामलों की तुलना में पीठासीन न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने और लम्बित मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में श्रम न्यायलयों के समक्ष जिले वार लम्बित मामलों की संख्या-

क्र. सं.	जिले का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1.	अहमदाबाद	32095
2.	गाधीनगर	113
3.	खेडा	5867
4.	साबरकांठा	1580
5.	वांसकांठा	2282
6.	मेहसाना	5865
7.	राजकोट	9095
8.	भावनगर	5874
9.	सुरेन्द्रनगर	4645
10.	अमरेली	1250
11.	जूनागढ़	4828
12.	जामनगर	6893
13.	कच्छ	1991
14.	वडोदरा	11128
15.	पंचमहल	3893
16.	भड़ौच	5374
17.	सूरत	12575
18.	डांग	-
19.	वलसाड	6507
	कुल	121851

1988 और 1997 के मध्य मामलों के लम्बन में वृद्धि हुई है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वहां पीठासीन अधिकारियों के 41 पद हैं जिनमें से 13 पद रिक्त हैं। गुजरात राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए उन्होंने त्वरित उपाय किये हैं। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 16 नये श्रम न्यायलयों की मंजूरी प्रदान की गई है। नवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1997-98 के लिए अमरेली में एक श्रम न्यायलय को मंजूरी प्रदान की गई थी।

ESIC Hospitals for workers

4358. SHRI C. RAMACHANDRIAH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that adequate number of ESIC hospitals are not there for the workers, benefit;

(b) if so, what steps are proposed in this financial year to open more hospitals; and

(c) details of such steps for the welfare of workers?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) At present, there are 127 ESI Hospitals and 43 Annexes functioning under the ESI Scheme in different parts of the country. Recently, the Corporation has constructed three more ESI Hospitals and handed over to the concerned State Governments for commissioning. In addition, there are 15 ESI Hospitals at various stages of construction. New hospitals under the ESI Scheme are constructed generally on the basis of need keeping in view the norms prescribed by the ESI Corporation. Accordingly, the Corporation has agreed, in principle, for construction of 12 additional hospitals at different places. Pending construction/completion of new ESI hospitals, necessary arrangement has been made with governmental and non-governmental institutions to provide general, speciality and super-speciality treatment to the ESI beneficiaries.

Per hod expenditure on children in special schools under NCLP

4359. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are proposing to raise the per head expenditure on children in Special Schools under NCLP, and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No Sir.

(b) Does not arise.